



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Handwritten signature and date: 14/12/88

सं. 619] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 1988/अग्रहायण 14, 1910
No. 619] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 1988/AGRAHAYANA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विद्युत संचालन

राजस्व विभाग

(विदेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1988

अधिसूचना

प्राय-कर

सा. का.नि. 1146(अ).--प्राय पर कर की भावना बौहरे कराधान का परिवर्तन और राजविस्तार अधिवसन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा विज मेजेस्टी की नेपाल सरकार के बीच हुए उपाबद्ध करार, करार को प्रवृत्त करने के लिए उनकी अपन-प्रपनी विधियों के अधीन प्रेषित प्रक्रियाओं के मूला होने पर और उक्त करार के अनुच्छेद 27 के अधीन दोनों संबिदाकारी रात्र्यों द्वारा प्रत्येक के लिए अधिसूचना जारी करने पर, तारीख 1 नवम्बर 1988 को प्रवृत्त हो गया है।

पान, प्रब, केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रवृत्त कृतियों का प्रयोग करते हुए।

निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत के संघ में प्रभावी किया जाएगा।

प्राय पर करों के संबंध में बौहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अधिवसन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल के श्री 5 के सरकार के बीच

करार

प्राय पर करों के संबंध में बौहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अधिवसन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल के श्री 5 के सरकार के बीच करार।

भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल के श्री 5 के सरकार प्राय पर करों

के संबंध में बोहरे कराधान के परिष्कार और राजस्व के अधिप्रेषण को रोकने के लिए एक करार संपन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अध्याय-I

करार का विषय-क्षेत्र

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों संबिदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद II

करार के अंतर्गत आने वाला कर

1. यह करार जित करों पर लागू होगा, वे निम्नलिखित हैं :-

(क) भारत के मामले में :

- (i) आयकर विधेय अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 111 में उल्लिखित कर्षणों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लगाए जाएंगे। संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
- (ii) कंपनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अध्याय 111 में उल्लिखित कर्षणों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लगाए जाएंगे। संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

(ख) नेपाल के मामले में :

- (i) आयकर अधिनियम, 2031 के अध्याय 111 में उल्लिखित कर्षणों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लगाए जाएंगे। संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अध्याय-II

परिभाषाएं

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में अब तक विषयगत पाठ में अथवा अपेक्षा नहीं की :-

- (क) "एक संबिदाकारी राज्य" और "दूसरे संबिदाकारी राज्य" शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा नेपाल अभिप्रेत है;
- (ख) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा नेपाल कर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें वह राशि शामिल नहीं होगी, जो उन करों, जिन पर यह करार लागू होता है, के संबंध में किसी भी कर अथवा भवनों के लिए देय होगी अथवा जो उन करों के संबंध में लागू हुए अधिप्रेषण की राशि होगी;
- (ग) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी और कोई अथवा सभा शामिल है, जिसे संबंधित संबिदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

(घ) "कंपनी" शब्द से कोई भी ऐसा नियमित निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता अभिप्रेत है, जिससे संबंधित संबिदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत किसी कंपनी अथवा नियमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ङ) "एक संबिदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संबिदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(च) भारत के मामले में "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और नेपाल के मामले में महा-महिम की सरकार, वित्त मंत्रालय अथवा उनका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(छ) "राष्ट्रिक" शब्द से कोई व्यक्ति जिसे संबिदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता प्राप्त हो तथा कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था जो संबिदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से इन प्रकार की प्रवृत्त हैसियत रखते हैं, अभिप्रेत है;

(ज) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों का अभिप्राय एक संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है जिसे इसके अंतर्गत कि जब वायुयान दूसरे संबिदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलता माना हो।

2. जहाँ तक किसी संबिदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, किसी शब्द का, जो इनमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विषयगत पाठ की अपेक्षा अपेक्षा नहीं होने पर वहाँ प्रयुक्त होगा, जो उन राज्य में उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत उनका अर्थ है, जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "किसी संबिदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति, जिन पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उनके अधिवस, निवास, प्रबंध स्थान अथवा इससे निवृत्त-भूतों किसी अन्य मानदंड के कारण कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

2. जहाँ पैरा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैसियत निम्नानुसार निश्चित होगी :-

- (क) वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई स्थायी गृह हो; यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्राथमिक गतिविधियां केन्द्रित हैं;
- (ख) यदि उसके पास किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो;
- (ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक आवास दोनों राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्राथमिक गतिविधियां केन्द्रित हैं;
- (घ) निवासास्पद मामलों में संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी मामले को परस्पर सहमति से हल करेंगे।

3. जहाँ पैरा 1 के उपबंधों के कारणों से, किसी व्यक्ति से निम्न कोई व्यक्ति दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संबिदाकारी

राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावों प्रबंध-व्यवस्था का स्थान निश्चित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. एक क़रार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ से उद्यम का कारोबार पूर्णतः प्रथम अंशान चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :--

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कर्मगाराना ;

(च) कोई खान, कोई सेन भवन या रीस कून, कोई खदान भवना प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई भवन-स्थल भवन निर्माण भवन एंसेम्बली परियोजना मेकिन केवल ऐसे जहाँ इस प्रकार के स्थान, परियोजनाएं भवन कार्यकलाप वारह महीनों की किसी अवधि के दौरान 183 दिन से अधिक की किसी अवधि भवन भवधियों के लिए चलते हों ;

(ज) किसी उद्यम द्वारा कर्मचारियों भवन अन्य कामियों की गार्कन सेवाएं प्रदान करना जहाँ देश के भीतर ऐसे कार्यकलाप वारह महीनों की किसी अवधि के दौरान 183 दिन से अधिक की किसी अवधि भवन भवधियों के लिए चलते हों ;

3. इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती उक्तियों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा ;

(क) उद्यम के माल भवन वाणिज्यिक वस्तुओं के माल भंडारण भवन प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग ;

(ख) केवल भण्डारण भवन प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल भवन वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टोक का रख-रखाव ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के उद्देश्य से उद्यम के माल भवन वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टोक का रख-रखाव ;

(घ) उद्यम के लिए केवल माल भवन वाणिज्यिक वस्तुओं को खरीदने भवन सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से कारखान के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव ;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक भवन सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप माल के प्रयोजनार्थ कारखान के किसी निर्धारित स्थान का रख-रखाव।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उक्तियों के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति, जो स्वतंत्र सिविल के किसी एजेंट, त्रिम पर पैराग्राफ 5 लागू होता है से भिन्न है, एक संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा उसके पास उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार है तथा वह उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, वहाँ उन उद्यम का उक्त राज्य में उन कार्यकलापों के संबंध में एक स्थायी संस्थापन होता माना जाएगा जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप उक्त उद्यम के लिए माल भवन वाणिज्यिक वस्तुओं को खरीदने तथा सूचना नहीं है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी प्नाल, सामान्य कर्मिणन एजेंट भवन स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम कारोबार करता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति भवन कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि जब ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः भवन लननन पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किये गये हों तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसे कम्पनी को नियंत्रित करती है भवन उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, भवन जो उस दूसरे राज्य में (जहाँ स्थायी संस्थापन के माध्यम से भवन भवन) कारोबार चलाती है, इन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

अध्याय-3

प्राय का क़राधान

अनुच्छेद-6

प्रचल सम्पत्ति से प्राय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित प्रचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि भवन वाणिज्यिक से प्राप्त प्राय भी शामिल है) से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. "प्रचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा, जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे--प्रचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वाणिज्यिक से प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भूसम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हैं प्रचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, खेत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए भवन संचालन के अधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय भवन नियत भवधियों के अधिकार। जनयान नौकाएं तथा वायुयान प्रचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध प्रचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने भवन किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की प्रचल सम्पत्ति से अर्जित प्राय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त प्रचल सम्पत्ति से अर्जित प्राय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारखान से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा किन्तु यह कर केवल उतने अंश पर लगेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, उस स्थायी संस्थापन को वह लाभ प्राप्त हुआ समझा जाएगा

जिसके प्राप्त होने की उस स्थिति में अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई भिन्न और अलग उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका वह स्थायी संस्थापन है।

3. (क) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उद्यम के ऐसे खर्चों की कटौती की अनुमति होगी जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजन के लिए किए गए हों जिनमें केवल कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च शामिल हों जैसे वे खर्च उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अग्र्यतः किए गए हों जो कि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के उपबंधों के अधीन अनुमत्य है जहां कि स्थायी संस्थापन स्थित है।

(ख) तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के प्रतिफल में रायस्टियों, फीस अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य भ्रमायगीय अथवा की गई विनिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध व्यवस्था के लिए कर्मोन्नत के रूप में अथवा बैंकिंग उद्यम के मामले में छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दी गई धन राशि पर ब्याज के रूप में प्रदत्त रकमों के सम्बन्ध में (जो वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न हों) ऐसी कटौती किए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय के पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के प्रतिफल में रायस्टियों, फीस अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य भ्रमायगीय अथवा की गई विनिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध व्यवस्था के लिए कर्मोन्नत के रूप में अथवा बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय को उधार दी गई धनराशि पर ब्याज के रूप में प्रदायित रकम (जो वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न हों) को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

4. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति संविदाजन के द्वाारा पर किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसे प्रबंधित विभाजन पद्धति से, कर लगाए जाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी, तथापि, उक्त संविदाजन पद्धति ऐसी होगी, कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए साल या वार्षिक वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्णानुवर्ण उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में भाग की ऐसी रकमें शामिल हों जिन पर इस करार के अन्य अनुच्छेदों में भ्रम से विचार किया गया है, उस स्थिति में उन अनुच्छेदों के उपबंधों पर इस अनुच्छेद के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 8

बायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय प्रचालन अधिकरण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से संबंधित विधियों पर ब्याज को ऐसे विमान परिवहन से प्राप्त लाभ/लाभ माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में धारा 1 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

4. "बायुयान परिवहन" पद का अर्थ यह होगा—बायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा प्रयोजकों 'चार्टर्स' द्वारा यात्रियों, डाक, पशुघन या माल का बायुयान से परिवहन का व्यापार, जिनमें अग्र्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, बायुयान का अनुसंगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी अन्य कार्य-कलाप शामिल है।

अनुच्छेद 9

संबंध उद्यम

जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं, और दोनों ही अकस्मातों में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हो, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की वशा में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तत्पश्चात् कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अथवा किसी अन्य राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में ही, जिसकी लाभांश अथवा करने वाली कम्पनी निवासी है और उस राज्य के कानून के अनुसार कराधेय होंगे, किन्तु यदि पाते वाला लाभांश का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार अभावमाने वाले कर --

(क) लाभांशों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यदि हितभागी स्वामी कोई कम्पनी है जिसके पास लाभांश देने वाला कम्पनी के शेयरों के कम-से-कम दस प्रतिशत शेयर हों;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" पद का अर्थ लाभांश अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त भाग से है जो अलग-थलग नहीं हों,

साधनों में भागीदार हों, तथा अन्य निम्नलिखित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर उसी प्रकार कर लगाया जाता है, जिस प्रकार कि उस राज्य के कराधान कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उन स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि साधारणों का हिस्सा स्वामी, जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिसकी साधारण प्रथा कर्मचारी कम्पनी निवासी है, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थान के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ उपलब्ध करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में साधारणों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थान अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में, यथा-स्थिति, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 13 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संबिदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संबिदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अथवा किए गए साधारणों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकेगा, केवल उस सीमा को छोड़कर जहाँ तक कि ऐसे साधारण उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहाँ तक कि वह धारणाधिकार जिसके संबंध में लभाधारों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए साधारण अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस प्रकार के दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संबिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संबिदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हिस्सा स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

तथापि, जहाँ यह है कि जहाँ ब्याज वास्तविक बैंकिंग व्यापार चलाने वाले उस बैंक को दिया जाता है, जो दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी है और जो ब्याज का हिस्सा स्वामी है, वहाँ जिस संबिदाकारी राज्य में ब्याज उद्भूत होता है उस राज्य में प्रभारित कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संबिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्त यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हिस्सा स्वामी के रूप में लखा गया हो ;

(i) दूसरे संबिदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक उप-प्रधान अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा

(ii) दूसरे संबिदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी बांधों से प्राप्त आय, चाहे वे ऋण द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के साधनों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त

आय-बंधनपूर्ण अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित साधारण और पुरस्कार शामिल हैं। विलम्ब से की गई अदायगी के लिए अर्थात् संबंधी प्रथारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उन स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हिस्सा स्वामी, जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संबिदाकारी राज्य में जिनमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ उपलब्ध करता है, और जिस ऋण-दाते के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 13 के उपबंध, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संबिदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाले स्वयं वह संबिदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रधान, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह संबिदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संबिदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा अदा किया जाता है तो हम प्रकार का ब्याज उन संबिदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिनमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ ब्याज अदाकर्ता तथा उनके हिस्सा स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अथवा की गई ब्याज की रकम, उन ऋण-दाते को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिनके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हिस्सा स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अतिरिक्त राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामलों में अदायगी के अतिरिक्त ध्यान पर, हम करार के अन्य उपबंधों का मन्वक अनुपालन करने हुए प्रत्येक संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

रायस्टियाँ

1. एक संबिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायस्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायस्टियों पर उस संबिदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानून के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायस्टी का हिस्सा स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायस्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायस्टियाँ" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फिल्में, अथवा रेडियो प्रदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, अथवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के प्रतिकूल के रूप में डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फामूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध इस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि राष्ट्रियों का स्थानाधीन स्वामी, जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिसमें राष्ट्रियों उद्भूत होती हैं, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से या वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्थित वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के संबंध में राष्ट्रियों भ्रवा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या 13 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो लागू होंगे।

5. एक संबिदाकारी राज्य में राष्ट्रियी तब उद्भूत मानी जाएगी, जब राष्ट्रियी भ्रवा करने वाला स्वयं वह राज्य, उग राज्य का कोई राज-नैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो या कोई निवासी हो। तथापि, जहाँ राष्ट्रियी भ्रवा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संबिदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, संबिदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन भ्रवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में राष्ट्रियी भ्रवा करने की वेनवारी उद्भूत हुई ऐसी राष्ट्रियी ऐसी स्थायी संस्थापन द्वारा भ्रवा निश्चित स्थान द्वारा बहुत की जाती हो, तो ऐसी राष्ट्रियी उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहाँ भ्रवाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच भ्रवाता उन दोनों के तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, राष्ट्रियी की राशि उपयोग, अधिकार और सूचना का प्याज में रखते हुए, जिसके लिए इसे भ्रवा किया जाता है, उस राशि ने बढ़ जाती है जो इस प्रकार का संबंध न होने की स्थिति में भ्रवाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा तय की गई होती, तो वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अतिम वर्णित राशि पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, भ्रवा भ्रवा की गई राशि पर करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ध्यावसायिक सेवाओं भ्रवा उनी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों द्वारा प्राप्त भ्राय पर निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी भ्राय पर दूसरे संबिदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा :

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संबिदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संबिदाकारी राज्य में केवल उनी भ्राय पर कर लगाया जा सकेगा जिसने उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी या उभती है; भ्रवा
- (ख) यदि उसकी दूसरे संबिदाकारी राज्य में टहरने की भ्रवाधि या भ्रवाधिया किसी संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" भ्रवा "भ्राय के वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल 183 दिन भ्रवा उतसे अधिक हो, उस मामले में, तो भ्राय के केवल उतने भाग पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उत दूसरे राज्य में निष्पादित उनके कार्यकलापों से उसे प्राप्त होती हो।

2. "ध्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिकों, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक भ्रवा भ्रवापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, आस्तुधियों, दस्त चिकित्सकों तथा लेखा-कारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 14

परामित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, और 20 के उपबंधों के अधीन रहने हुए, एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा भ्रवी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि नियोजन किसी दूसरे संबिदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उतसे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संबिदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" भ्रवा "भ्राय के वर्ष" में जीना भी सामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की भ्रवा भ्रवाधियों के लिए उन दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; तथा
- (ख) पारिश्रमिक, ऐसे नियोजन द्वारा या उसकी ओर से भ्रवा किया जाता है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो; और
- (ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा बहुत नहीं किया जाता हो जो नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी, एक संबिदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वातायान में पारि-भालित किसी हवाई जहाज पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15

निवेशकों की फीस

एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संबिदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गयी निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य भ्रवाधियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ियों द्वारा भ्रवित भ्राय

अनुच्छेद 13 और 14 के उपबंधों के होने हुए भी, एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे पिघेटर, शलचित्र, रेडियो भ्रवा दूरदर्शन कलाकार या संगीतकार भ्रवा खिलाड़ी के रूप में दूसरे संबिदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त भ्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जब किसी मनोरंजनकर्ता भ्रवा खिलाड़ी द्वारा किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में अपनी इस प्रकार की हैसियत से प्राप्त भ्राय मनोरंजनकर्ता भ्रवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, प्रपित किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो अनुच्छेद 7, 13 और 14 के उपबंधों के होने हुए भी, उस भ्राय पर कर उस संबिदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्ता भ्रवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों को हटाने हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में इस प्रकार के लिए गए उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोत्प्लिखित सविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि दूसरे सविदाकारी राज्य में उन कार्य कलापों को प्रथमोत्प्लिखित सविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिनमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई उप-प्रभाग, अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी जाती है।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 13 और 14 के उपबन्धों को हटाने हुए भी, जहां मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपनी इन प्रकार की हस्तियत से किसी सविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ऐसे मामले में उस आय पर उस स्थिति में केवल दूसरे सविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा यदि उस अन्य व्यक्ति को दूसरे सविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिनमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी जाती है।

अनुच्छेद 17

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी सविदाकारी राज्य, अथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग या प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में पेंशन से भिन्न अथवा किए गए पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे सविदाकारी राज्य में उसी स्थिति में ही कर लग सकेगा, यदि वे जहाँ दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :-

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) सेवाएं अर्पित करने मात्र के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवसि नहीं बना

2. (क) किसी सविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में उस सविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण द्वारा मंजूर निधियों में से किसी व्यक्ति को अदा की गयी किसी भी पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर उस स्थिति में केवल दूसरे सविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा यदि व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो और राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 14, 15 और 16 के उपबन्ध, किसी सविदाकारी राज्य या उसके राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कारोबार के बारे में की गयी सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 18

पर सरकारी पेंशन और वाधिक्रिया

1. एक सविदाकारी राज्य को किसी निवासी द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य को खोती से प्राप्त अनुच्छेद 17 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किसी वाधिक्रिया पर कर केवल प्रथमोत्प्लिखित सविदाकारी राज्य में ही लगाया जाए।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियत कालिक भुगतान से है, जो विगत में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. "वाधिक्रिया" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो घन अथवा घन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के लिए दायित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अथवा विनिश्चित अथवा निश्चय्य समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर मासिक रूप से देय हो।

अनुच्छेद 19

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे सविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले सविदाकारी राज्य में से किसी एक का निवासी है अथवा था तथा वह उस दूसरे राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, उस दूसरे सविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:

(क) उस दूसरे सविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उससे की गई अदायगियां; तथा

(ख) उस दूसरे सविदाकारी राज्य में किसी "विगत वर्ष" अथवा "आय वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर जो 18,000 रु. (आठतीस हजार) अथवा नेपाली मुद्रा में उसके समतुल्य से अधिक न हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे संबंधित हो अथवा उसके भरण पोषण के प्रयोजनार्थ शुरू किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए मिलेगा जो प्रारंभ की गई शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा आवश्यकता अवधि हो, परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को उसके उस दूसरे सविदाकारी राज्य में प्रथम बार उसके पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 20

अध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे सविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल में अथवा दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस दूसरे सविदाकारी राज्य में पहुंचने से तुरन्त पहले सविदाकारी राज्य में से किसी एक का निवासी है अथवा था, उस दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अतिरिक्त की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे सविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद उन शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के मित्रों के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 19 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक सविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में यथा स्थिति, वह दूसरे सविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" के तुरन्त पहले उस सविदाकारी राज्य का स्थित हो।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त" संस्था का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के गणम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई हो।

अनुच्छेद 21

अन्य शाय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की ऐसी मदें, जहाँ कहीं वे उद्भूत होती हैं और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराघेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अवल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगी, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के माते दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी नियमित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिनके सम्बन्ध में ऐसी आय प्राप्त की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 13 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

अध्याय 4

दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए प्रणाली

अनुच्छेद 22

दोहरे कराधान का अपाकरण

संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून उन संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ इस करार में उनके विरुद्ध कोई उपबंध किए जाते हैं। जहाँ आय पर दोनों राज्यों में कर लगता हो वहाँ इस अनुच्छेद के अनुसार दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जाएगी।

2. नेपाल से बाहर किसी क्षेत्र में संदेय कर को नेपाली कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में नेपाल के कानून के उपबंधों के अध्येक्षित (जो इसके सामान्य सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करेंगे), भारत के कानून के अंतर्गत और इस करार के उपबंधों के अनुसार, भारत में स्त्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय भारतीय कर आय की उम्मीदों के संदर्भ में जिन पर भारतीय कर की गणना की जाती है, संगणित की गई नेपाली कर की रकम के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी।

3. पैराग्राफ (2) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए शब्द "देय भारतीय कर" में वह राशि शामिल समझी जाएगी जिसकी निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन उपायों द्वारा कर में कटौती की जाएगी:—

- (1) भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4क), 10(6) (ii), 10(5) (iv), 10(28), 10क, 32क, 33क, 80अ, 80अक, 80अख, और 80ड ;
- (ii) कोई अन्य उपबंध जो बाद में कर से ऐसी कटौती प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया जाए, जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए सहमत हों।

4. भारत से बाहर किसी क्षेत्र में देय कर की भारतीय कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में भारत के कानून के उपबंधों

के अध्येक्षित (जो इसके सामान्य सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करेंगे) नेपाल के कानून के अंतर्गत और इस करार के उपबंधों के अनुसार नेपाल में स्त्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय नेपाली कर, आयकर की उम्मीदों के संदर्भ में जिन पर नेपाली कर की गणना की जाती है, की गई भारतीय कर की गणना के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी।

जहाँ कि ऐसी देय राशि भारतीय कर (ऐसी देय राशि की स्वीकृति देने से पहले की गई गणना के अनुसार) से अधिक नहीं होगी जो कि नेपाल में स्त्रोतों से प्राप्त आय के विनियोज्य होगी। तथापि, जहाँ पर ऐसा निवासी वह कम्पनी ही जिसके द्वारा भारत में अतिकर देय हो, वहाँ भारत में कम्पनी द्वारा देय आयकर के प्रति उपर्युक्त जमा की स्वीकृति प्रथमतया दी जाएगी और यदि कोई शेष राशि होगी, तो उसके लिए कम्पनी द्वारा भारत में देय अतिकर के प्रति स्वीकृति दी जाएगी।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रयोजनार्थ "संदेय नेपाली कर" में ऐसी कोई रकम शामिल की गई समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए नेपाली कर के रूप में संदेय हो गई होती परन्तु उस वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए निम्नानुसार कर में दी गई छूट अथवा उसमें की गई कटौतियों के कारण ऐसा नहीं हुआ :

(क) नेपाल आयकर अधिनियम, 2031 (1974) की धारा 42 की उपधारा (2), जिस हद तक यह प्रवृत्त थी और तब से उस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख तक संगोपन नहीं किया गया हो या उसमें मामूली-मा संशोधन किया गया हो ताकि उसके उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हो; अथवा

(ख) कोई अन्य उपबंध जिसे कर से छूट प्रदान करने अथवा उसमें कटौती करने के बाध बनाया जाए जिसके लिए सक्षम प्राधिकारियों में सहमति होती है और जो काफी हद तक उन्नी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि इसे उसके पश्चात् संगोपित नहीं किया गया हो अथवा इसमें मामूली-मा संशोधन किया गया हो ताकि इससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

6. जहाँ इस करार के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अन्य संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट दी जाती है, तब प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करते समय कर की वह दर लगाएगा जो उस अवस्था में लागू होती यदि इस करार के अनुसार कर से छूट प्राप्त आय पर कर से छूट प्राप्त नहीं हुई होती।

अध्याय 5

विशेष उपबंध

अनुच्छेद 23

समन्वयवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, तथा तत्संबंधी अपेक्षाएँ जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक-समान परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान

परिस्थितियों के अधीन समस्त कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राहत, कटौतियां तथा भट्टीसियां मंजूर करके, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहाँ के निवासी हैं, उपहृत करना है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के पर्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रयोजित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से अथवा तत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है जो प्रयोजित राज्य के अन्य समस्त उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों के अधीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 24

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझे कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाही के परिणामस्वरूप उस पर बह कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, जो प्रस्तुत करार के अनुषंग नहीं है तो इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का वह निवासी है, उसके सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस को प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस कार्यवाही के कारण ऐसा कर लगाया जाता है जो करार के अनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होगी और यदि वह स्वयं कोई उचित समाधान निकालने में असमर्थ होगा तो, वह ऐसे फलदान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुषंग नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार सम्पन्न कोई भी करार कार्यविधि किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस करार की व्यवस्था करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। ये उन मामलों में दोहरे कराधान के अभावरूप के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी करार पर पहुँचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जब सहमत होने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें वस्तुनिष्ठ भी शामिल हैं) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उप-

बंधों की अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यविधि करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अन्तर्गत प्राप्ते हैं, जहाँ तक कि इनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जाससाजी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए करार के प्रतिकूल नहीं हो। किसी भी संविदाकारी-राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार सूचित मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक-लिकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनको वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बंध हों, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे परियोजनाओं के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित भाँती, पत्रियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहाँ कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा वस्तुनिष्ठों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के स्वरूप में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर, ऐसी सूचना अथवा वस्तुनिष्ठों की सूची से सहमत होंगे, जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित धातव्य डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा वस्तुनिष्ठों की सत्यापन करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा वस्तुनिष्ठों की सत्यापन करना जिनसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद 26

राजनयिक और कौंसली कार्यकलाप

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक कौंसली अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 6

अन्तिम उपबन्ध

अनुच्छेद 27

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे राज्य की इस करार को लागू करने के लिए इसके कानूनों द्वारा अपेक्षित कार्यविधि की समाप्ति को अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित पर प्रवृत्त होगा:

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में बाव वाली अधिसूचना दी जाती है, उस वर्ष में परवर्ती धर्म के प्रथम दिन को प्रथम उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ती किसी वर्ष में उद्भूत आय के सम्बन्ध में ;

(ख) नेपाल में, जिस कैलेंडर वर्ष में बाव वाली अधिसूचना दी जाती है, उस वर्ष के अगले परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को प्रथम उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में ।

प्रसूचित 28

समाप्ति

यह कठोर अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसरे दिन को या उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को, समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा, और ऐसी स्थिति में यह कठोर निम्नलिखित के सम्बन्ध में निष्प्रभावी हो जायेगा :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उस वर्ष के अगले परवर्ती अप्रैल के प्रथम दिन को प्रथम उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत आय के सम्बन्ध में ;

(ख) नेपाल में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को प्रथम उसके बाद प्रारंभ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधिकारियों ने इस कठोर पर हस्ताक्षर किए हैं ।

काठमांडौ में वर्ष एक हजार भी सो सतासी के जनवरी मास के अठारवां दिन को हिन्दी, नेपाली और संज्ञेयी भाषाओं में, दो प्रतियों में किया गया । व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में संज्ञेयी पाठ ही प्रभावी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार नेपाल के भी 5 के- सरकार की ओर से

(नारायण बल तिवारी) (मैलेन्द्र कुमार उपाध्याय)
विदेश मंत्री परराष्ट्र तथा सूचिसुधार मंत्री

[ए. 8138 का. सं. 11/4/88-एफ. टी. डी.]

पी. के. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 5th December, 1988

INCOME-TAX

NOTIFICATION

G.S.R. 1146(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal for

the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on 1st November, 1988, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 27 of the said Agreement, of the completion of procedures required under their respective laws for bringing the Agreement into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT OF NEPAL
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE

TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal.

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income :

Have agreed as follows :

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in the case of India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) in the case of Nepal :

(i) income-tax imposed under the Income-Tax Act, 2031 (hereinafter referred to as "Nepal tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantial similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Nepal, as the context requires;
- (b) the term "tax" means Indian tax or Nepal tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit, under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Nepal, His Majesty's Government, Ministry of Finance or their authorised representative;
- (g) the term "national" means by any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State in which his economic activities are concentrated;
- (b) if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State in which his economic activities are concentrated;
- (d) in case of dispute, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

- (g) a building site or construction or assembly project, but only where such site, project or activity continues for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period;
- (h) the furnishing of services by an enterprise through employees or other personnel, where activities continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of the Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise,
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of an activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. (a) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, expenses of the enterprise which are incurred for the purpose of the permanent establishment, including only those executive and general administrative expenses incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or

elsewhere which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards re-imbusement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments, in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees, or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income/profits

derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected

to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, not subject the company's undistributed profits, to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

Provided, however, that where the interest is paid to a bank carrying on bonafide banking business, which is resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or

not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for the radio

or television broadcasting any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived

from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 15, 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad on an aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 15

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 16

INCOME-EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 13 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artist or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 13 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 13 and 14, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 17

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who

(i) is a national of that State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 18

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 17, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth

ARTICLE 19

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 18,000 (Indian currency), or its equivalent in Nepalese currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 20

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this article and article 19, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 21

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement. Where income is subject to tax in both Contracting States relief from double taxation shall be given in accordance with this Article.

2. Subject to the provisions of the law of Nepal regarding the allowance as a credit against Nepal's tax of tax payable in a territory outside Nepal (which shall not affect the general principle hereof) Indian tax payable under the law of India and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within India shall be allowed as a credit against any Nepal tax computed by reference to the same items of income by reference to which the Indian tax is computed.

3. For the purpose of the credit referred to in paragraph (2), the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which tax has been reduced by the special incentive measures under —

- (i) Sections 10(4), 10 (4A), 10 (6) (viiia), 10 (15) (iv), 10 (28), 10A, 32A, 33A, 80HH, 80HHA, 80-I and 80-L of the Indian Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
- (ii) any other provision which may subsequently be enacted granting a reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof) Nepal tax payable under the law of Nepal and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within Nepal shall be allowed as a credit against any Indian tax computed by reference to the same items of income by reference to which Nepal tax is computed.

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Nepal, so however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

5. For the purpose of paragraph (4) of this Article the term "Nepal tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Nepal tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) sub-section (2) of section 42 of the Nepal Income-tax Act, 2031 (1974), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

6. Where under this Agreement a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first mentioned Contracting State may in calculating tax on the remaining income of that person apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with the Agreement had not been so exempted.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 23

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State;

- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 26

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreement.

CHAPTER VI-

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 27

ENTRY INTO FORCE.

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

ARTICLE 28

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before

the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Kathmandu on this eighteenth day of January, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN A.D. in Hindi, Nepali and English languages all the texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
(NARAYAN DATT TIWARI)
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

GOVERNMENT OF NEPAL
FOR HIS MAJESTY'S
(SHAIENDRA KUMAR UPADHYAYA)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
AND LAND REFORMS
GOVERNMENT OF INDIA

[No. 8198]F. No. 11/4/69-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

